

भारत सरकार
पंचायती राज मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं.795
दिनांक 28 अप्रैल, रार्थको उत्त 2016

पंचायतों को वित्तीय सहायता

795. श्री रामचरण बोहरा :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार का विचार पंचायतों को सीधे वित्तीय सहायता प्रदान करने का है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी योजना-वार ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस प्रस्ताव के कब तक कार्यान्वित होने की संभावना है ?

उत्तर

**पंचायती राज, राज्य मंत्री
(श्री निहाल चंद)**

(क) से (ग) जी, हां । चौदहवां वित्त आयोग (एफएफसी) ने ग्राम पंचायतों को वर्ष 2015 से 2020 की अनुदान अवधि के लिए 2,00,292.20 करोड़ रु. की राशि के अनुदान की सिफारिश की है। इस अनुदान का उपयोग जल आपूर्ति, सेप्टेज प्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवरेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, तूफान के जल की निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपथों और गलियों में प्रकाश व्यवस्था का रख-रखाव, तथा कब्रिस्तान और श्मशान घाट सहित बहुत सी बुनियादी सेवाओं की स्थिति में सुधार लाने पर किया जाना है। इसके अलावा, आयोग ने पंचायतों के अपने संसाधनों का आधार बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों द्वारा कुछ उपाय करने की सिफारिश भी की है। 90 प्रतिशत अनुदान मूल अनुदान और 10 प्रतिशत निष्पादन अनुदान (वर्ष 2016-17 से लागू) होंगे। वित्त मंत्रालय तय दिशा-निर्देशों के अनुसार विभिन्न राज्यों को अनुदान आबंटित व जारी करता है। वर्ष 2015-16 के दौरान ग्राम पंचायतों के लिए अनुदानों का राज्य-वार कुल अनुदान और उन्हें जारी की गई राशि के ब्यौरे अनुबंध में दिए गए हैं ।

अनुबंध

ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों (मूल एवं निष्पादन) का आबंटन एवं जारी की गई राशि

पंचायतों को वित्तीय सहायता के विषय में दिनांक 28.04.2016 को उत्तरार्थ लोक सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 795 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में संदर्भित अनुबंध राशि करोड़ रूपए में

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2015-20 के लिए कुल आवंटन	वर्ष 2015-16 के दौरान निर्मुक्ति
1	2	3	4
1	आंध्र प्रदेश	8654.09	928.41
2	अरुणाचल प्रदेश	819.92	44.26
3	असम	5416.58	292.40
4	बिहार	21017.83	2269.18
5	छत्तीसगढ़	5244.13	566.18
6	गोवा	133.77	7.22
7	गुजरात	8634.73	932.25
8	हरियाणा	3883.52	419.28
9	हिमाचल प्रदेश	1809.80	195.39
10	जम्मू एवं कश्मीर	3463.73	367.72
11	झारखंड	6046.74	652.83
12	कर्नाटक	9288.66	972.36
13	केरल	4017.61	216.88
14	मध्य प्रदेश	13556.36	1463.61
15	महाराष्ट्र	15035.68	1623.32
16	मणिपुर	206.04	22.25
17	मेघालय	0.00	0.00
18	मिजोरम	0.00	0.00
19	नागालैंड	0.00	0.00
20	ओडिशा	8850.31	955.52
21	पंजाब	4091.13	220.85
22	राजस्थान	13633.63	1471.95

23	सिक्किम	148.49	16.04
24	तमिलनाडु	8777.43	947.65
25	तेलंगाना	5375.28	580.34
26	त्रिपुरा	335.68	36.24
27	उत्तर प्रदेश	35776.56	3852.60
28	उत्तराखंड	1882.69	203.26
29	पश्चिम बंगाल	14191.78	735.43
	कुल	200292.20	19993.42